P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

खाद्यान्न उत्पादन में चुनौतियाँ एवं दृष्टिकोण : जनपद कुशीनगर के विशेष संदर्भ में

अरविन्द कुमार
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कुशीनगर, उ0प्र0
(दी0द0उ0 गोरखपुर
विश्वविद्यालय, गोरखपुर),
भारत

कौस्तुभ नारायण मिश्र
असोसिएट प्रोफेसर
भूगोल विभाग,
बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
कुशीनगर (उ0प्र0)।
(दी0द0उ0 गोरखपुर
विश्वविद्यालय, गोरखपुर),
भारत

सारांश

भारत में खाद्यान्न उत्पादन में ह्रास के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 2011–12 में खाद्यान्न का उत्पादन 259.32 लाभ टन की रिकार्ड ऊँचाई पर था। यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली हैं जब आम तौर पर यह मान्यता है कि दुनिया के कई हिस्सों में कृषि कार्य पर अपर्याप्त ध्यान दिए जाने के कारण खाद्य कमी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र वृद्धि होगी। इसकी तुलना में भारतीय कृषि ने मुख्य रूप से समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के कारण अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि भारत धान, गेहूँ, दलहन, गन्ना, मसालें और वृक्षारोपण फसलों जैसी कई प्रमुख फसलों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, उत्पादकता स्तरों के मामले में तुलना विश्वसनीय नहीं है, इन फसलों में से कई में बहुत कम रैंक हासिल है, इसके अलावा अध्ययन दर्शाते है कि देश में विभिन्न फसलों में काफी अधिक उत्पादकता अन्तर है। कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है अगर हम तकनीकी और नीति उपायों को अपनाकर इस उपज अन्तराल को समाप्त करे। भारत के लिए खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर रहने के लिए पैदावार में सुधार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई कृषि फसलों और उत्पादों में खुद की जगह बनाने के लिए मुख्य है।

मुख्य शब्द : उत्पादों, उत्पादन, खाद्य, खाद्यान्न, वृक्षारोपण, कृषि, प्रौद्योगिकी, फसल बीमा, पोषण, पोषण–स्तर।

प्रस्तावना

हमारे कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक तीव्रता वाली मौसम सम्बन्धी घटनाओं और आवृत्ति के गंभीर निहितार्थ हो सकते है और खाद्य उत्पादन एवं उसके द्वारा किसानों की आजीविका के सम्बन्ध में अधिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकते है। वर्तमान फसल बीमा प्रणाली को अपरिहार्य जलवायु परिस्थितियों या कीट महामारी को समाप्त करने के लिए और अधिक परिष्कृत किए जाने की जरूरत है।

भारत में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट चिंता का प्रमुख विषय रहा है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि ही महत्वपूर्ण नहीं है, वरन् आम आदमी के भोज की थाली में खाद्य वस्तुओं की सही मात्रा सुनिश्चित करना भी है।

खाद्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बागवानी उत्पादों और प्रोटीन–प्रचुर मदों पर जोर दिया जाना आवश्यक है। कुशीनगर नव सृजित जनपद है, जहाँ पर नहरें अधिक होने के कारण गेहूँ की फसल ज्यादा मात्रा में वर्बाद हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नहरों की मरम्मत एवं रख–रखाव नहीं हो पाती है। इस प्रकार से मात्र दो ही प्रधान फसल है एक धान दूसरा गन्ना। क्षेत्र के लोगों को ज्यादातर एक ही फसल उगाने के कारण अन्य खाद्यान्न वाली फसलों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन क्षेत्र में पूर्वी और उत्तरी–पूर्वी क्षेत्रों में कृषि विकास की गति बाकी क्षेत्रों (हिस्सों) की तुलना में धीमी रही है। अध्ययन क्षेत्र के इन हिस्सों में कई फसलों में उत्पादन की अच्छी संभावनाओं का आने वाले वर्षों में जल्दी से लाभ उठाना चाहिए। अतः पूर्वी और उत्तरी–पूर्वी कुशीनगर में कृषि विकास के कार्यनीति लागू किए जाने की जरूरत है, जिसने खेती प्रणाली एप्रोच के माध्यम से स्थापित कृषि विकास के लिए कार्यनीति, कुशल राष्ट्रीय संसाधन प्रबन्धन पर्यावरण क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी मिशन और चावल, गन्ना आधारित खेती–प्रणाली लागू हो।

परिकल्पनायें

1, खाद्यान्न उत्पादन में उन्नतिशील बीज, सिंचाई के साधन, मृदा संरक्षण एवं पोषण के बीच साहचर्य आवश्यक होता है।
2, कृषि फसलों हेतु विश्वसनीय कृषि सांख्यिकी का सुदृढ़ीकरण और समय पर उपलब्धता प्रमुख आवश्यकता होती है।

विधि तन्त्र एवं उपागम

इसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ा स्रोत का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक सूचनाओं का संग्रह क्षेत्र के भौगोलिक पृष्ठभूमि जनसंख्या, मानव अधिवास, कृषि जोत भूमि आदि से सम्बन्धित सूचनायें विभिन्न प्रकाशित स्रोतों और सरकारी अभिलेखों से एकत्रित किया गया है और प्राथमिक स्रोत से उसकी पुष्टि की गयी है।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के धुर पूर्वोत्तर में बिहार से संलग्न $26^0$34′ उत्तर से $27^0$17′ उत्तरी अक्षांश एवं $83^0$32′ पूर्व से $84^0$15′ पूर्वी सीमा बिहार राज्य की सीमा देवरिया जनपद दक्षिण–पश्चिम सीमा गोरखपुर जनपद उत्तर प्रदेश सीमा महराजगंज की सीमा से निर्धारित होती है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2373.5 वर्ग किमी0 है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है।

मुख्य अध्ययन वस्तु

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन

अध्ययन क्षेत्र में कृषि विपणन में आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन है। खराब सड़कों, बाजार के अल्पविकसित बुनियादी ढाँचे और अत्यधिक विनियमों के कारण किसानों की बाजारों में पहुँच में बाधा आती है।

ग्रामीण परिक्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन में चुनौतियाँ

अध्ययन क्षेत्र में कृषि फसलों की प्रकृति जल्दी खराब होने की होती है और कटाई के उपरान्त निपटान के मुद्दों और विपणन की समस्याएँ कृषि आय को प्रभावित करती है। यह आवश्यक है कि हम कृषि उत्पादन गति विधियों के साथ प्रसंस्करण लॉजिस्टिल और खुदरा विक्री को जोड़ने के लिए एक तंत्र विकसित करे, जिससे कि वर्धित दक्षता बेहतर कृषि मूल्य आदि का सृजन किया जा सके। इन बाजार लिंकेजो के विकास कार्य में निजी क्षेत्र को अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए उपरोक्त सुधार से मदद मिलेगी। हाल ही में सरकार के द्वारा खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ0डी0आई0) के अनुमति दी है जिसका कई किसान संगठनों द्वारा भी समर्थन किया गया है और इसमें नई प्रौद्योगिकी और कुशीनगर में कृषि उपज के विपणन में निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है –

1. रोजगार और जीविका के साधन उपलब्ध कराना।
2. जीवन–स्तर में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना।
3. प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना।
4. खेती और किसान को मुख्य धारा से जोड़ना इत्यादि।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन से प्रत्यक्ष लाभ

कुछ किसान अपनी उपज मंडियों में ले जाते है, परन्तु ज्यादातर किसान स्थानीय आढ़तियों को या उपज खरीदने वालों को बेच देते है, हालांकि यह किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन के न्यूनतम मूल्य का संकेत होता है। खाद्य सब्सिडी के रूप में इस प्रक्रिया में काफी लागत लगती है। इसके अलावा, वफर मापदण्डों के ऊपर खाद्यान्नों की जमाखोरी की यह नीति जमाखोरी और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर और उसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी करने के आधार पर आलोचना के अन्तर्गत आती है। कुशल खाद्य भण्डार, प्रबन्धन, समय पर शेयरों की विकवाली और एक स्थिर और पूर्वकथन योग्य व्यापार नीति पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

खेती के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ

भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकता के प्रति सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। समय की माँग है कि खेती को लेकर वैचारिक शिथिलता और संस्थागत निष्क्रियता को खत्म किया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने बीते दिनों में एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधनों की कमी की ओर बढ़ते विश्व में खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डाला गया था। तकनीक के बढ़ते प्रयोग ने किसानों के लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावनाएं पैदा की है। रिपोर्ट के अनुसार तकनीक के प्रयोग से सन् 2050 तक वर्तमान उत्पादन क्षमता में 67 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अन्न की कीमत में 50 प्रतिशत तक कटौती सम्भव है।

खाद्यान्न उत्पादन में ई–खेती का जमाना

डिजिटल ग्रीन नामक एक गैर–सरकारी संगठन छोटे किसानों की सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार के साथ–साथ कृषि प्रणाली में सुधार के लिए अभिनव तरीके विकसित करने की दिशा में कार्यरत है। विगत दिनों में शुरू हुए किसान टी0वी0 को इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा हैं गूगल 'प्ले स्टोर पर भी तमाम ऐसे एप्लीकेशन उपलब्ध है, जो न केवल खेत–खलिहान से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराते है, बल्कि सरकारी अथवा गैर–सरकारी स्तर पर हो रहे विभिन्न प्रयोगों कार्यक्रमों नीतिगत बदलावों आदि की भी सूचना देते रहते है। खेती ई–ज्ञान, माडल खेती, एग्रो इंडिया, एग्रीएप, किसान योजना अग्रोवन कृषि एवं कृषि मित्र आदि कई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जायेगा।

खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि हेतु अभिनव प्रयोग

तकनीकी उपकरणों की मदद से अब खेती से जुड़े कई मामलों में सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। खेती में उर्वरकों के उचित प्रयोग के लिए सिंचाई के लिए कटाई अथवा बुआई के लिए छोटे द्रोण जैसे नवीन उपकरणों और (J.P.S.) जे0पी0एस0 सुविधा का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे खेती को आसानी से नवीगेट कर सही जगह का पता लगाया जा सके और निगरानी रखी जा सके। कृषि क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मोनसेंटों और उपकरण निर्माता जानडीरे कंपनी की योजना बड़ी कृषि उत्पादन कंपनियों को नवीनतम कृषि अपडेट वृहद–स्तर पर किए डाटा खनन के पश्चात् उपलब्ध कराने की है।

इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसान तकनीक के उपयोग की ओर आकृष्ट होगें। इस दिशा में असल चुनौती तकनीक शून्य ग्रामीण समाज को इसके प्रयोग से अवगत कराना सहज करना और सुलभ कराना होगा। अधिकांश प्रशिक्षकों में क्लाउड कंप्यूटिंग, एम–लर्निंग स्वामित्व की कुल लागत जैसे सामान्य विषय पर जानकारी का अभाव पाया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन 'खाद्यान्न उत्पादन में चुनौतियाँ एवं दृष्टिकोण–जनपद कुशीनगर के विशेष सन्दर्भ में' का प्रमुख उद्देश्य किसी पिछड़े क्षेत्र या जनपद में खाद्यान उत्पादन की चुनौतियों को रेखांकित कर उसके प्रति नागरिकों, सम्बन्धित किसानों, उपभोक्ताओं, उत्पादकों, विपणनकर्ताओं एवं सरकार के दृष्टिकोण को समझना और खाद्यान्न उत्पादन को आवश्यकता एवं प्रकृति उपागम तथा माँग–आपूर्ति आधारित बनाने की आधारभूत सरंचना तैयार करने पर आधारित है।

निष्कर्ष

ग्रामीण को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का स्वप्न गांधी के ग्राम स्वराज से लेकर आधुनिक समय के स्मार्ट विलेज तक की यात्रा तय कर रहा है, लेकिन धरातल पर देखे तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि यह दौर संक्रमण का है, अतः विगत कुछ योजनाओं में निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा और ग्लोबज विलेज के दायरे में खीचने का कार्य किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

स्रोत – खाद्यान्न भूगोल, भूगोल और आप, वर्ष–12, अंक–70, सितम्बर–अक्टूबर 2013, पृ0 45–47

पाण्डेय संदीप कुमार, ''डिजिटल होता ग्रामीण भारतः वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की रूपरेखा, कुरूक्षेत्र, Vol. 63, No.10 अगस्त 2017, पृ0 45–48

मिश्र प्रशांत, ''ग्रामीण भारत में जश्न के जतन'', दैनिक जागरण, 2 फरवरी, 2018, पृ0 3

आम बजट– 2018–19, दैनिक जागरण, फरवरी 2018, पृ0 4

आम बजट– 2018–19, हिन्दुस्तान, फरवरी 2018, पृ0 6

शाह, रमेश, ''कृषि केन्द्रित बजट से बढ़ेगी विकास क्षेत्र'' दैनिक जागरण फरवरी 2018, पृ0 4

सौरभ समीरा, ''भारतीय कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी'' कुरूक्षेत्र Vol. 63, No. 10, 2017, पृ0 27–28

नित्नाज्मा घोव, ''कृषक कल्याण का निश्चय : एक सपना और हकीकत'', योजना, Vol. 61, No. 7, 2017, पृ0 27–30